Based on the recommendation of Selection Committee, the Kendriya Vidyalaya Sangathan has issued offers of appointment to 83 candidates.

Starvation deaths

2690. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received any report on death due to starvation from the State Governments and Union Territories during the last four years; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Cultivation of Soyabean

2691. DR. SHRIKANT RAM CHANDRA JICHKAR:
DR. BAPU KALDATE:
SHRI JAGIR SINGH DARD:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of the States where the cultivation of Soyabean is being undertaken;

(b) the total area of land brought under such cultivation during each of the last three years; yearwise;

(c) the total production of soyabean during the above period, state-wise;

(d) the steps being taken by Government to increase the cultivation of Soyabean; and

(e) the details of the progress made in setting up of soyabean based industries like (Soya-milk, Soya-Cheese) etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): (a) The major soyabean growing States are Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Karnataka and Gujarat.

(b) and (c) State-wise area and production for the last three years is given in the Statement (*See* below).

(d) To increase the cultivation of oilseeds including soyabean, Oilseeds Production Programme (OPP) is under implementation in 22 States covering 337 districts. Assistance is provided under OPP for production and distribution of seeds, distribution of sprinkler sets, improved farm implements, Rhyzobium culture and PSB, gypsum and pyrites, etc. Further, to propagate the production technology, frontline demonstrations are organised by the ICAR and block demonstrations by the State Departments of Agriculture.

(e) Much progress has not been made in setting up of soyabean based industries like soya-milk and soya-cheese. Some entrepreneurs have started production of soya products on a limited scale. However, 98 soyabean processing industries have been set up with an installed capacity of 70 lakh tonnes per annum.

Statement

Area & Production under soyabean cultivation During Last Three Years

State	AREA (THOUSAND HECTARES)			PRODUCTION (THOUSAND TONNES)		
	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
Andhra Pradesh	2.6	4.5	6.0	2.3	5.0	5.0
Gujarat	17.0	18.4	20.0	11.7	14.0	14.0
Himachal Pradesh	0.9	0.8	18.0	0.3	0.3	5.0
Karnataka	41.3	37.8	47.0	27.0	33.5	42.0
Madhya Pradesh	3054.0	3289.5	2910.0	2598.9	3480.3	2587.0
Maharashtra	365.0	501.7	561.0	361.4	671.4	526.0
Orissa	0.9	0.9	1.0	0.6	0.6	1.0
Rajasthan	264.8	345.5	403.0	333.4	369.9	443.0
Uttar Pradesh	30.4	36.1	33.0	37.9	36.7	35.0
Others	11.8	12.3	11.0	13.4	14.6	14.0
Total	3788.7	4247.5	4010.0	3386.9	4626.3	3672.0

बाल-विवाह

†2692. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने बाल-विवाह हुये हैं;

(ख) देश में बाल-विवाहों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा): (क) देश में आयोजित बाल-विवाहों की संख्या के बारे में कोई सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध नही है। तथापि, वर्ष 1994-95 के दौरान "बाल विवाह निषेध अधिनियम" के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है **(नीचे देखिए)**

(ख) सरकार ने बाल-विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1976 पारित किया है जिसके अन्तर्गत लड़कों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिये 18 वर्ष रखी गयी है। इस अधिनियम को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। विधायी उपायों के अलावा सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से देश में बाल-विवाहों के विरुद्ध जन प्रचार कार्यक्रम तेज कर दिये हैं। छोटी आयु में विवाह और गर्भधारण से लड़की के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव के बारे में स्वैच्छिक अभिकरणों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित जागरूकता विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामाजिक चेतना उत्पन्न की जा रही है।

(ग) बाल-विवाह निषेध अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों के लिये दण्डित व्यक्तियों की संख्या के बारे में सांख्यिकी सूचना संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान बाल-विवाह निषेध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994	1995 माह तक
1	2	3	4 5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	1 अगस्त
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0 सितम्बर
3.	असम	1	0 अप्रैल
4.	बिहार	9	1 मई
5.	गोआ	0	0 अक्तूबर
6.	गुजरात	20	10 जून
7.	हरियाणा	2	0 जुलाई